

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
31.07.2024 के
तारांकित प्रश्न सं. 123 का उत्तर

अधूरी रेल अवसंरचना परियोजनाएं

*123. श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक रेल अवसंरचना परियोजनाएं विभिन्न कारणों से अधूरी पड़ी हैं;
- (ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में निर्धारित समय से पीछे चल रही ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) ये परियोजनाएं कब से निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को और समय गंवाए बिना और लागत में वृद्धि किए बिना पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

अधूरी रेल अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को लोक सभा में श्री अरविंद गणपत सावंत और श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे के तारांकित प्रश्न सं. 123 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल परियोजनाएं राज्य-वार/संघ शासित प्रदेश-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत की जाती हैं क्योंकि भारतीय रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में, लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए की लागत पर कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (187 नई लाइन, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक, लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

सभी रेल परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेल-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

भारतीय रेल में नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	11,527 करोड़ रु. प्रति वर्ष	-
2024-25	68,634 करोड़ रु.	लगभग 6 गुना

भारतीय रेल में नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण खंडों की कमीशनिंग का ब्यौरा निम्नानुसार है -

अवधि	कमीशन किए गए कुल रेलपथ	कमीशन किए गए औसत रेलपथ	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	7,599 किलोमीटर	4.2 किलोमीटर प्रति दिन	-
2014-24	31,180 किलोमीटर	8.54 किलोमीटर प्रति दिन	2 गुना से अधिक

2023-24 में भारतीय रेल में 5,309 कि.मी. खंड कमीशन किए गए हैं।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 81,580 करोड़ रुपए की लागत से 5,877 कि.मी. कुल लंबाई की 41 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (16 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण) क्रियान्वयन/सहमति के चरण में हैं, जिसमें से 1,926 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 31,236 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- i. 38,423 करोड़ रु. की लागत पर 2,017 कि.मी. कुल लंबाई की 16 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 166 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 8,529 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।
- ii. 7,339 करोड़ रु. की लागत पर 609 कि.मी. कुल लंबाई की 2 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिनमें से 312 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 3,332 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।
- iii. 35,818 करोड़ रु. की लागत पर 3,251 कि.मी. लंबाई की 23 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से 1,448 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 19,376 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

इसके अलावा, उपनगरीय गलियारों पर संकुलन से बचने और भावी मांगों को पूरा करने के लिए, 10,947 करोड़ रुपये की लागत वाले एमयूटीपी-III और 33,690 करोड़ रुपये की लागत वाले एमयूटीपी-IIIए को स्वीकृत किया गया है। इन परियोजनाओं में निम्नलिखित 10 अतिरिक्त रेल लिंक शामिल हैं :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु. में)
1	सीएसटीएम-कुर्ला 5वीं एवं 6ठी लाइन (17.5 कि.मी.)	891
2	मुंबई सेंट्रल-बोरीवली 6ठी लाइन (30 कि.मी.)	919
3	पनवेल-करजत उपनगरीय गलियारा (29.6 कि.मी.)	2782
4	एरोली-कलवा (एलीवेटेड) उपनगरीय गलियारा लिंक (3.3 कि.मी.)	476
5	विरार-दहाणु रोड की 3री एवं 4थी लाइन का चौहरीकरण (64 कि.मी.)	3587
6	हार्बर लाइन गोरेगांव-बोरीवली का विस्तार (7 कि.मी.)	826
7	बोरीवली-विरार 5वीं एवं 6ठी लाइन (26 कि.मी.)	2184
8	कल्याण-आसनगांव के बीच 4थी लाइन (32 कि.मी.)	1759
9	कल्याण-बदलापुर के बीच तीसरी और चौथी लाइन (14.05 कि.मी.)	1510
10	कल्याण यार्ड-मेन लाइन और उपनगरीय लाइन का पृथक्करण	866

इन सभी एमयूटीपी परियोजनाओं को रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच लागत में 50:50 भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है। बहरहाल, महाराष्ट्र सरकार 2022-23 तक प्रतिबद्धता के अनुसार समय पर अपेक्षित धनराशि उपलब्ध नहीं करा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2023 से एमयूटीपी-IIIए परियोजनाओं का वित्तपोषण शुरू कर दिया है।

2014 से भारतीय रेल में परियोजनाओं के निधि आबंटन और तदनुरूपी उनकी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	1,171 करोड़ रु. प्रति वर्ष	-
2023-24	13,539 करोड़ रु.	11.56 गुना
2024-25	15,940 करोड़ रु.	13.61 गुना

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की कमीशनिंग का ब्यौरा निम्नानुसार है -

अवधि	कमीशन किए गए कुल रेलपथ	कमीशन किए गए औसत रेलपथ	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	292 किलोमीटर	58.4 किलोमीटर प्रति वर्ष	-
2014-24	1830 किलोमीटर	183 किलोमीटर प्रति वर्ष	3.13 गुना

2023-24 में कुल 358 कि.मी. को कमीशन किया गया है, जो 2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में 6 गुना से अधिक है।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं (i) निधियों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि, (ii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (iv) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव क्लियरेंस के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करना।

रेल परियोजना (परियोजनाओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत वहन परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत की हिस्सेदारी जमा कराने, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना (परियोजनाओं) के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।
